Journal Homepage: www.ijarpr.com ISSN: 3049-0103 (Online)

International Journal of Advance Research Publication and Reviews

Vol 02, Issue 08, pp 550-553, August 2025

शिक्षा में कौशल विकास एवं वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता

डॉ. दिनेश कुमार मौर्य

एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, एम.एल.के.पी.जी. कॉलेज बलरामपुर *(उत्तर प्रदेश)*

भूमिका

भारत सरकार ने "कौशल भारत मिशन (SIM)" के अंतर्गत कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न अभिसरण प्रयास शुरू किए हैं। इस मिशन के अंतर्गत, 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुसार कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर स्कूली बच्चों सहित लाखों लोगों के कौशल स्तर को बढ़ाने हेतु कौशल विकास योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और मुख्यधारा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे छात्रों को उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न कौशल हासिल करने में मदद मिलेगी।

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) कौशल भारत मिशन के उद्देश्यों के साथ संरेखित करते हुए, केन्द्र प्रायोजित योजना - समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्कूल शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ एकीकृत करना; छात्रों की रोजगारपरक और उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ाना, कार्य वातावरण से परिचित कराना; और छात्रों में विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जागरूकता पैदा करना है ताकि वे अपनी योग्यता, क्षमता और आकांक्षाओं के अनुसार चुनाव कर सकें। इस योजना में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय शामिल हैं।

संकेत शब्द-- व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा नीति, कौशल विकास, उद्यमशीलता |

इस योजना के अंतर्गत, एनएसक्यूएफ अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को योजना के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में प्रदान किए जाते हैं। माध्यमिक स्तर, अर्थात् कक्षा 9वीं और 10वीं, पर विद्यार्थियों को व्यावसायिक मॉड्यूल एक अतिरिक्त विषय के रूप में प्रदान किए जाते हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर, अर्थात् कक्षा 11वीं और 12वीं, पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम एक अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में प्रदान किए जाते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन अनुमानित घंटों, निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता तथा स्कूली विद्यार्थियों की उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अन्य शैक्षणिक विषयों के समान माना जाए और विषयों की योजना में उन्हें समान दर्जा दिया जाए।

इस योजना के तहत, रोज़गार कौशल मॉड्यूल को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। इसमें संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE), शिक्षा मंत्रालय (MoE) के सहयोग से, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (PMKVY 3.0) के अंतर्गत 'कौशल हब पहल' योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। कौशल केंद्र, स्कूल छोड़ने वाले और शिक्षा से वंचित छात्रों को लक्षित कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए चिन्हित नोडल कौशल केंद्र हैं। कौशल केंद्रों के माध्यम से एकीकृत कौशल विकास को लागू करने की दिशा में एक कदम के रूप में, 1 जनवरी, 2022 से एक पायलट परियोजना शुरू की गई है।

शिक्षा में कौशल विकास)Skill Development in Education) एक महत्वपूर्ण विषय है जो छात्रों को वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह शिक्षा को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर, व्यावहारिक और रोजगारउन्मुख कौशल प्रदान करने पर केंद्रित है।- शिक्षण सभी व्यवसायों की जननी है। शिक्षण, छात्रों को विभिन्न चयनित अनुभवों के माध्यम से उपयुक्त शिक्षणअधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने की जटिल कला है। अच्छा शिक्षण कड़ी मेह-नत और अथक प्रयासों का परिणाम है। यह बच्चों को स्वयं को और अपनी क्षमताओं की पूरी श्रृंखला को खोजने में मदद करने के उत्साह से भरा एक पेशा है। शिक्षण के लिए योग्यता आवश्यक है। पाठ की योजना बनाने, पाठ की प्रस्तुति, शिक्षण को समाप्त करने या समाप्त करने, अपने छात्रों की क्षमताओं का मूल्यांकन करने, कक्षा का प्रबंधन करने और अनुशासन बनाए रखने में योग्यता। एक शिक्षक की शिक्षण योग्यता, शिक्षक के पास मौजूद ज्ञान, क्षमताओं और विश्वासों के समूह को संदर्भित करती है और उसे शिक्षण स्थिति में लाती है। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई शिक्षण कौशल शामिल होते हैं। यह निर्देशात्मक उद्देश्यों के एक निर्दिष्ट समूह की प्राप्ति के लिए घटक कौशलों का एक समूह है। शिक्षण कौशल विशिष्ट शिक्षण गतिविधियाँ और प्रक्रियाएँ हैं जिनका उपयोग एक शिक्षक अपनी कक्षा में कर सकता है। शिक्षकों की योग्यता, संवेदनशीलता और प्रेरणा, शिक्षार्थियों की उपलब्धि की गुणवत्ता और सीमा के निर्धारक कारक हैं। एक तरह से, किसी देश में शिक्षा की गुणवत्ता और मानक इस बात पर निर्भर करते हैं कि वह अपने शिक्षकों के व्यावसायिक विकास का प्रबंधन कैसे करता है। शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है और शिक्षकों की गुणवत्ता उनके द्वारा प्राप्त कौशल पर निर्भर करती है। शिक्षकों की उचित शिक्षा के बिना कोई भी शिक्षा कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। अच्छे शिक्षकों के बिना, सर्वोत्तम व्यवस्था भी असफल हो सकती है। अच्छे शिक्षकों के साथ, किसी भी व्यवस्था की कमियों को भी काफी हद तक दूर किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षकों को सर्वोत्तम

संभव कौशल प्राप्त हों ताकि वे शिक्षा के समग्र स्तर को ऊपर उठाने में योगदान दे सकें। इस शोध पत्र के माध्यम से लेखक ने विभिन्न शिक्षण कौशलों और दक्षताओं पर प्रकाश डाला है, जो शिक्षणअधिगम प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत में 100 प्रतिशत स्कूलों में कौशल शिक्षा को जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है जिनमें से कम से-कम - 50 प्रतिशत छात्रों का नामांकन 2030 तक होगा.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति)NEP), 2020 तीन आवश्यक वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार करती है जिनके लिए शैक्षिक प्रतिक्रिया ज़रूरी हैसबसे पहले उभरती तकनीकें जैसे कि मशीन लर्निंग ., बिग डेटा और जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस)AI) कल के काम करने वालों .और बड़े स्तर के कौशल की मांग करती है (सीखने का तरीका सीखना) में अनुकूलनशीलता (वर्कफोर्स) दूसरी बात ये है कि जलवायु परिवर्तन, घटते प्राकृतिक संसाधन और प्रदूषण की वजह से पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां दुनिया में खाद्य, पानी, ऊर्जा और स्वच्छता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनोवेटिव और टिकाऊ समाधानों की मांग करती हैंतीसरा ., नई तरह की बीमारियों, महामारियों और संक्रामक रोगों के बढ़ते ख़तरे के कारण बेहतर चिकित्सकीय अनुसंधान और आर्थिक सामर्थ्य की आवश्यकता उत्पन्न होती है इन चुनौतियों के लिए तैयारी के उद्देश्य से .NEP शुरुआती कक्षाओं से ही नए युग की कौशल केंद्रित शिक्षा को प्राथमिकता देती है जो अलग.अलग विषयों के दृष्टिकोण का लाभ उठाती है और सैद्धांतिक क्लासरूम के ज्ञान को व्यावहारिक प्रयोग के साथ जोड़ती है-

कौशल शिक्षा को लागू करने की दिशा में कदम

शुरुआती उम्र से कौशल शिक्षा को लागू करने के लिए भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय बोर्ड यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), जिसके साथ 30,634 स्कूल जुड़े हुए हैं, ने महत्वपूर्ण पहल की है. मिडिल ग्रेड्स यानी कक्षा छह से लेकर आठ के बीच CBSE ने 33 विषयों जैसे कि कोडिंग, डेटा साइंस, डिज़ाइन थिंकिंग और मास मीडिया पर 12-15 घंटे के स्किल मॉड्यूल की शुरुआत की है. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं (IX-XII) में छठे वैकल्पिक (इलेक्टिव) विषय के रूप में 42 विषयों की सूची में से किसी एक कौशल वाले विषय को चुना जा सकता है. इन विषयों को भविष्य में करियर लाभ और छात्रों को रोज़गार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से विशिष्ट राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (NSQF) के अनुरूप तैयार किया गया है. 10 जनवरी 2025 के एक नीतिगत अपडेट के अनुसार अगर छात्र किसी वैकल्पिक विषय में फेल होते हैं तो शैक्षिक विषय के अंक को कौशल विषय के मार्क्स से बदल सकते हैं. इससे छात्रों को अपनी शैक्षिक यात्रा में अधिक लचीलापन मिलता है.

स्कूलों गें कौशल शिक्षा को जोड़ने के CBSE के दृष्टिकोण गें तीन पहलू उभर कर सागने आते हैं. पहला, ये अत्याधुनिक तकनीकों जैसे कि 3D (थ्री-डाइगेंशनल) प्रिंटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, AI के साथ-साथ पारंपरिक विषयों जैसे कि कश्मीरी कढ़ाई, पॉटरी (मिट्टी के बर्तन बनाना) और हर्बल विरासत पर कोर्स की पेशकश करता है. दूसरा, ये आस-पास के संदर्भ में काम-काज की संभावना के हिसाब से स्कूलों को एक लचीला पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करके छात्रों के कौशल विकास की मांगों को स्थानीय उद्योगों की ज़रूरतों के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है. तीसरा, उद्योग जगत की हस्तियों के साथ मिलकर CBSE इन विषयों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम का डिज़ाइन, पढ़ाई का संसाधन और मार्गदर्शन (हैंडहोल्डिंग) एवं परामर्श (मेंटॉरशिप) कार्यक्रम सक्रिय रूप से मुहैया कराता है.

अगस्त 2024 में CBSE ने ख़ुद से जुड़े स्कूलों को ज़रूरी औज़ार और तकनीक के साथ कंपोज़िट स्किल लैब (समग्र कौशल प्रयोगशाला) स्थापित करने का निर्देश दिया. तीन साल के भीतर स्थापित होने वाली इन प्रयोगशालओं का उद्देश्य छात्रों को लगातार व्यावहारिक अनुभव और उद्योग से जुड़ी ट्रेनिंग प्रदान करना है.

दूसरे बोर्ड जैसे कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन (CISCE) भी नए युग के विषयों की शुरुआत करके और उद्योगों के उभरते रुझानों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली जैसे संस्थानों से साझेदारी करके कौशल शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं.

पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस तरह के मिले-जुले प्रयासों ने भविष्य की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए भारत की तैयारी को बेहतर बनाया है. इस तरह QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत दुनिया में 25वें पायदान पर आ गया है जबकि "फ्यूचर ऑफ वर्क" सूचकांक में भारत उल्लेखनीय रूप से दूसरे स्थान पर है.

कौशल शिक्षा से लाभ

हर साल 97 लाख संभावित कामगारों को श्रम बल (लेबर फोर्स) में जोड़ने वाले भारत को शुरुआती स्तर पर कामगारों को हुनरमंद बनाने की पहल से बहुत अधिक सामाजिक-आर्थिक लाभ हासिल होगा. एक शुरुआती लाभ पढ़ाई के दौरान सीख और उसके व्यावहारिक, वास्तविक दुनिया में प्रयोग के बीच अंतर को पाटना है जिससे भविष्य के कामगार अधिक तैयार और रोज़गार के योग्य बन सकें. बढ़ईगीरी (कारपेंटरी), खेती, मार्केटिंग और सेल्स जैसे कौशल के विषय छात्रों को कक्षा में मिली जानकारी को ठोस तरीके से व्यवहार में लाने की अनुमति देते हैं. इस तरह एक समग्र और आकर्षक सीखने का अनुभव मिलता है.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT 2017) के द्वारा कराए गए एक प्रभाव अध्ययन (इंपैक्ट स्टडी) में पता चला कि रोज़गार के लायक हुनर हासिल करने के अलावा कौशल शिक्षा ने छात्रों को रोज़गार में बने रहने, पढ़ाई-लिखाई में दिलचस्पी, परीक्षण के परिणामों और आत्मविश्वास के स्तर को बेहतर बनाने में मदद की. अलग-अलग करियर के रास्तों की तरफ शुरुआती जानकारी से छात्रों को अपनी दिलचस्पी और प्रतिभा का पता लगाने में मदद मिलती है. इससे उन्हें उद्योगों की आवश्यकताओं के साथ अपने हुनर को जोड़ने का अवसर मिलता है.

वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स से पता चलता है कि भारत छात्रों को AI, ग्रीन (हरित) और डिजिटल स्किल में तैयार करने में पिछड़ रहा है. भारत में शुरुआती कौशल शिक्षा के स्तर में सुधार होने के साथ ही इस कमी का जल्द ही समाधान हो सकता है. उदाहरण के लिए, वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2024-25) में CBSE से जुड़े 4,538 स्कूलों के 8,00,000 से ज़्यादा छात्रों ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर AI कोर्स की पढ़ाई करने को चुना है जो भविष्य के हिसाब से तैयार हुनर के लिए मांग में बढ़ोतरी को दिखाता है.

तकनीकी क्षमताओं के अलावा कौशल शिक्षा संचार, रचनात्मकता, तालमेल और समस्याओं को सुलझाने जैसे जीवन से जुड़े ज़रूरी हुनर को भी बढ़ावा देती है. ये विकास की सोच को आगे ले जाती है, साथ ही अनुकूलनशीलता, सामर्थ्य और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है जो बदलते पारंपरिक नौकरी के बाज़ार और नए उद्योगों के उभरने के साथ तेज़ी से महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं. उदाहरण के तौर पर, कई छात्र पारंपरिक शैक्षणिक विषयों को भविष्य में अपने रोज़गार के लिए महत्वपूर्ण नहीं मान सकते हैं लेकिन वो ऑनलाइन आवेदन जमा करने, प्रोफेशनल ई-मेल लिखने, बुनियादी हिसाब-किताब और ई-बिल तैयार करने जैसे रोज़गार के लिए आवश्यक हुनर सीखने की इच्छा रख सकते हैं.

बाज़ार के हिसाब से तैयार कामगार घरेलू रोज़गार की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ दुनिया में हुनरमंद श्रमिकों की कमी, विशेष रूप से बुज़ुर्ग होती आबादी से जूझ रहे विकसित देशों में, दोनों का बेहतर ढंग से समाधान करने के लिए भारत को तैयार करेंगे. ग्लोबल नॉर्थ (विकसित देश) तेज़ी से हुनरमंद पेशेवरों की सप्लाई के लिए भारत जैसे आबादी के मामले में युवा देशों पर निर्भर होता जा रहा है. अगर भारत अपने कौशल पाठ्यक्रम में वैश्विक मानकों को जोड़ता है और अपनी कौशल शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाज़ार की ज़रूरतों के अनुसार रणनीतिक रूप से बनाता है तो वो उद्योग 4.0 के युग में वैश्विक वर्कफोर्स के एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को मज़बूत कर सकता है.

भारत में कौशल शिक्षा की राह में बाधाएं

समर्थ बनाने वाली नीतिगत स्थितियों के बावजूद भारत को कौशल शिक्षा के मामले में कम-से-कम तीन व्यापक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है. सबसे पहले भारत में बुनियादी ढांचा और संसाधनों की कमी है. शिक्षा के लिए एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली (UDISE+) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश भर में केवल 57.2 प्रतिशत स्कूलों में काम करने वाले कंप्यूटर हैं, 53.9 प्रतिशत स्कूलों में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी है, 55.9 प्रतिशत माध्यमिक स्कूलों में एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधा है और मात्र 17.5 प्रतिशत स्कूलों में कला और शिल्प की सुविधाएं हैं. ये कमियां कौशल शिक्षा को छात्रों तक पहुंचाने में बाधा बन सकती हैं.

दूसरा, ज़्यादातर स्कूलों में कौशल का पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए शिक्षक पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं. CBSE के द्वारा क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों और संसाधन विकास के बावजूद स्कूल अपने पाठ्यक्रम में रोबोटिक्स या AI जैसे नए युग के कोर्स को जोड़ने में जूझ रहे हैं. उदाहरणों से पता चलता है कि छात्रों तक ये कोर्स पहुंचाने के लिए स्कूलों ने निजी वेंडर से तालमेल की तरफ रुख़ किया है. लेकिन ये वंचित क्षेत्रों के छात्रों के लिए सामर्थ्य और पहुंच का सवाल खड़ा करता है

इसके अलावा तीसरी बाधा भारत की सख्त स्कूल प्रणाली है जो शैक्षणिक विषयों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है. हो सकता है कि अभिभावक और शिक्षक कौशल शिक्षा के महत्व को पूरी तरह से नहीं समझ पाएं. इसके अलावा ये भी हो सकता हे कि स्कूल इस तरह की पहल के लिए पर्याप्त समय नहीं दें क्योंकि वो माध्यमिक कक्षाओं में बोर्ड परीक्षा के प्रतिस्पर्धी दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हैं. पारंपरिक रास्तों के विपरीत कौशल शिक्षा को अक्सर उन छात्रों के लिए बाद के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है जो मुख्यधारा की पढ़ाई-लिखाई में जूझते रहते हैं.

आगे का रास्ता

भारत के स्कूलों में कौशल की शिक्षा लेने वाले सिर्फ 4 प्रतिशत छात्र हैं जबकि पश्चिमी देशों के साथ-साथ दूसरे एशियाई देशों में ये अनुपात बहुत ज़्यादा है

कौशल शिक्षा की इस स्पष्ट आवश्यकता और NEP के द्वारा निर्धारित मानदंडों को देखते हुए कई सरकारी और बहुपक्षीय एजेंसियों को भारत में कौशल शिक्षा के प्रभावी एकीकरण के उद्देश्य से सिफारिश पेश करने के लिए प्रेरित किया गया है. इनमें बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और कौशल केंद्रों के रूप में विशाल, बुनियादी ढांचे के मामले में सक्षम स्कूलों की स्थापना करके कौशल शिक्षा की पेशकश का विस्तार करने की ज़रूरत शामिल है. बाद में ये अपने आस-पास के छोटे स्कूलों के साथ हब एंड स्पोक मॉडल (एक मुख्य केंद्र और उससे जुड़े दूसरे संगठन) का पालन करते हुए जुड़ सकते हैं और सभी स्कूलों तक कौशल शिक्षा का विस्तार कर सकते हैं.

इसके अलावा पाठ्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से उपकरण, संसाधन और तकनीकी मार्गदर्शन मुहैया कराने में मदद के लिए निजी-सार्वजनिक साझेदारी (PPP) पर भी विचार किया गया है. तेज़ी से पहुंच और गुणवत्ता के भरोसे के लिए अलग-अलग हितधारकों यानी शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों, उद्योग, सिविल सोसायटी समूहों, CSR (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) एवं बहुपक्षीय संस्थानों के बीच समन्वित कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है.

इस परिदृश्य में एक संतुलित दृष्टिकोण बरकरार रखने के लिए सतर्कता बरतना महत्वपूर्ण है. सबसे पहले, कौशल शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार करने और नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के अभियान में कभी-कभी क्वालिटी से जुड़े मानकों की अनदेखी हो सकती है. शिक्षकों की अपर्याप्त तैयारी, ज़रूरत से कम निगरानी और कमज़ोर मान्यता प्रणाली कार्यक्रम को प्रभावहीन कर सकती है जिसका नतीजा रोज़गार के लिए छात्रों के तैयार नहीं होने और कौशल एवं उद्योग की मांग के बीच अंतर बरकरार रहने के रूप में निकल सकता है.

एक और मुश्किल पाठ्यक्रम को गतिशील बनाए रखना और उसे उद्योग की बदलती आवश्यकता के अनुसार लगातार ढालना है. तेज़ी से बदलते दुनिया के श्रम बाज़ार और तकनीकी प्रगति के कारण ये ज़रूरी हो गया है कि कौशल शिक्षा को प्रासंगिक बने रहने के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उद्योग के हितधारकों एवं श्रम बाज़ार के विश्लेषण से मिले रियल-टाइम फीडबैक को शामिल करना चाहिए. इसके तहत पाठ्यक्रम में लगातार अपडेट के साथ लचीली कोर्स संरचना और शैक्षिक संस्थानों एवं उद्योग जगत की हस्तियों के बीच मज़बूत साझेदारी शामिल है. इस तरह के उपाय सुनिश्चित करते हैं कि छात्र नौकरी के बाज़ार की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए ज़रूरी योग्यता रखते हैं.

अंत में, एक महत्वपूर्ण ख़तरा गुणवत्तापूर्ण कौशल शिक्षा तक असमान पहुंच है जहां वंचित छात्र को बुनियादी ढांचे की कमी, डिजिटल बंटवारे और ख़राब बुनियादी साक्षरता एवं अंकगणित (FLN) से जुड़े परिणामों का सामना करना पड़ता है. इसलिए मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट, स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड और समुदाय आधारित कार्यक्रमों जैसे लक्षित हस्तक्षेप के बिना कौशल शिक्षा स्कूल की पढ़ाई-लिखाई में मौजूदा असमानताओं को दूर करने की जगह उन्हें और गहरा कर सकती है.

उपसंहार –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति)NEP) 2020 में कौशलआधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है-, जिसका उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। इसके तहत, छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान, समस्यासमाधान-, आलोचनात्मक सोच, और रचनात्मकता जैसे कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। NEP 2020 में, कौशल आधारित शिक्षा-को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने की बात कही गई है, ताकि छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

1. आर .ए.दुबे, आर्थिक विकास एवं नियोजन, नेशनल पब्लिशर्य हाउस नई दिल्ली
2. जैन, डॉ.एम.के ., शोध विधियाँ, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2016
3. डॉचतुर्भुज मामोरिया भारत की आर्थिक समस्याएँ ., साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूट्स 2017-18
4. डॉओ.पी. शर्मा ., भारत में नियोजित विकास और आर्थिक उदारीकरण, रामप्रसाद एण्ड संस 2022-23
5. उद्यमी, उद्योग और स्वरोजगार चतुर्थ संस्करण उद्यमिता केन्द्र -उ प्र.2019
6. भारत की जनगणना जनसंख्या के अनंतिम आंकड़े -, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 2021
7. Patel L. and Shah Nimish (2014), “India's Skills Challenge: Reforming Vocational Education and Training to Harness the Demographic Dividend”. ISBN-10: 0199452776, ISBN-13: 978-0199452774.
8. Shrivastava P., Techno-Vocational Skills Acquisition and Poverty Reduction Strategies, ISBN13: 9783659363672 ISBN10: 3659363677, Publisher: LAP
9. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट,) उ(.प्र.
10. दैनिक समाचार, दैनिक भास्कर, राज एक्सप्रेस, पत्रिका 2025।
11. डॉप्रमिला कुमार ., म प्र. का भौगोलिक अध्ययन म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी.2000
12. डॉ .बी.एल .गुप्ता, सांख्यिकी, साहित्य भवन पब्लिशर्स डिस्ट्रन्यूटर्स 2025
13. डॉडी.एन. चतुर्वेदी ., डॉपी.सी. सिन्हा ., आर्थिक शोध के तल, लोक भारती प्रकाशन 2023
14. कटरिया रस्तागी, सांख्यिकी सिद्धान्त एवं व्यवहार पब्लिकेशन मेरठ 2022
15. एसके. मिश्रा बी.के. पुरी., भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस 2017
16. शर्मा वीरेन्द्र प्रकाश, रिसर्च मेथडोलांजी, पंचशील प्रकाशन जयपुर 2024